

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

89 / 2023 प्रा.पत्र / 2023

29.08.2023

22.12.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1—श्री अर्जुन लाल अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल अग्रवाल निवासी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स संजय मार्केट व्यास पेट्रोल पम्प के पीछे मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड—304502 मोबाईल नं. 9252208273
- 2—मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स संजय मार्केट व्यास पेट्रोल पम्प के पीछे मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड—304502
- 3—श्रीमति विनीता माहेश्वरी पत्नि श्री राकेश माहेश्वरी निवासी 116 टैगोर नगर, अजमेर रोड, वैशाली नगर जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स रविश बेवरेजेज इण्डस्ट्रीयल प्लॉट नं. एच—127, रघुनाथपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया अराई जिला अजमेर राज.। पिनकोड—305801
- 4—मैसर्स रविश बेवरेजेज इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. एच—127, घुनाथपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया अराई जिला अजमेर राज.। पिनकोड—305801

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

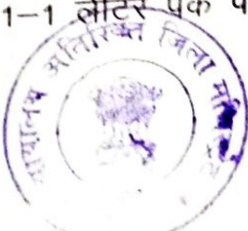
- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थीगण की ओर निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री गोविन्द गुप्ता उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 22.12.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.01.2023 को समय 04:00 पीएम पर मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स संजय मार्केट व्यास पेट्रोल पम्प के पीछे मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री अर्जुन लाल अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अर्जुन लाल अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान के गोदाम में कागज के 150 कार्टूनों में लगभग 1200 मूल पैक बोतल पैकड अवस्था में प्रत्येक कनग 1-1 लीटर पैक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्वा बिस ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा



1780

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अर्जुन लाल अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अर्जुन लाल अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ऐक्वा बिस ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर ए-19 एवं पैकिंग की दिनांक 02/01/2023 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 1-1 लीटर पैक के 16 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ऐक्वा बिस ब्राण्ड) 1-1 लीटर पैक के 16 मूल पैक में से ज्यों का त्यों 4-4 बोटलों को धागे से बांधकर अलग-अलग नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3425 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3425 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अर्जुन लाल अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल अग्रवाल ने बतौर वारन्टी मैसर्स रविश बेवरेजेज इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. एच-127, घुनाथपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया अराई जिला अजमेर का वारन्टी बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/258 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./131/एक्ट/2023/196 दिनांक 24.01.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ऐक्वा बिस ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री गोविन्द गुप्ता उपस्थित हुए एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र लेबल पर आवश्यक जानकारी अंकित नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ऐक्वा बिस ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ऐक्वा बिस ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.12.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)  
न्याय निणयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0